शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 20 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 09 – 16 मई 2022 मूल्य पांच रूपए

क्या यह कानून की समझ है या अदालत का सम्मान

कसौली कांड में अदालत द्वारा नामितों के खिलाफ क्यों नही हो पायी कारवाई

डवैल्पमैन्ट प्लान पर एन जी टी का फैसला

शिमला/शैल। एनजीटी ने जयराम सरकार द्वारा तैयार की गई शिमला डवैल्पमैन्ट प्लान के कार्यान्वयन के संदर्भ में उस पर कोई भी कदम उठाने पर अपने 12 मई के फैसले में तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इसकी किसी भी अवहेलना के लिये मुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराने के आदेश किये गये हैं। स्मरणीय है कि शिमला में निर्माणों को लेकर लगातार अवहेलनाएं होती रही है। सरकार और नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर इस संदर्भ में बनाये गये अपने ही नियमों की अनुपालना नहीं होती रही। सरकारें स्वयं रिटैन्शन पॉलिसीयां लाकर अपने ही बनाये नियमों को अंगूठा दिखाती रही। निर्माण अवैधताओं को नियमित करने के लिए नौ बार ऐसी पॉलिसियां लायी गयी। शिमला के साथ ही कुल्लू-मनाली, कसौली और धर्मशाला भी इन अवैधताओं के शिकार होते गये। क्योंकि नगर नियोजन और ग्रामीण विकास विभाग बनाकर 1980 में प्रदेश के लिये जो अन्तरिम डवैल्वमैन्ट प्लान जारी किया गया था उसे आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। हर सरकार पर आरोप लगते रहे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कई फैसलों में सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है। लेकिन सरकार पर कभी कोई असर नहीं हुआ। स्थितियां कसौली कांड घटने तक पहुंच गयी। मामला एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अदालत ने इस कांड के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को नामतः चिन्हित करते हुये उनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये। जिन पर आज तक कोई कारवाई नहीं हो सकी है। क्योंकि शासन- प्रशासन में बैठे कई लोग स्वयं इन अवैधताओं के दोषी हैं।

हथधर्मिता की हद तो यह है कि यह सब उस प्रदेश में हो रहा है जो भूकंप जोन पांच में आता है। प्रदेश की राजधानी शिमला का रिज और लक्कड़ बाजार का जो एरिया 1971 में किन्नौर में आये भूकंप से ध्वस्त हुआ था वह आज तक रुक नहीं पाया है। ऐतिहासिक रिज हर वर्ष प्रभावित हो रहा है। भूगर्भीय अध्ययनों के अनुसार शहर का बहुत हिस्सा स्लाईडिंग और सिंकिंग जोन घोषित है। लेकिन वोट की राजनीति के चलते इस हिस्से में भी निर्माण नहीं रुके हैं। पूरे प्रदेश के ऊपर पर्यावरण से खिलवाड़ का जो असर पड़ा है उसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के किसी न किसी भाग में रोज भूकंप आ रहे हैं। शिमला में ही एक हल्के से झटके से चालीस हजार से ज्यादा जान माल का नुकसान होने की चेतावनी सरकार अपनी ही रिपोर्टो में दे चुकी है। लेकिन जब सरकार ने अपनी ही रिपोर्टो पर अमल नहीं किया तब एक योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता ने इस सब को एन जी टी के समक्ष एक याचिका के माध्यम से उठाया। एन जी टी का 16-11 2017 को इस पर फैसला आ गया। यहां यह भी गौरतलब है कि यह फैसला प्रदेश सरकार के सचिवालय में बैठे अपने ही उच्चअधिकारियों की रिपोर्टो के ऊपर आधारित है। इन रिपोर्टो में प्रधानमंत्री के वर्तमान सलाहकार तरुण कपूर की रिपोर्ट विशेष महत्वपूर्ण है।

एन जी टी का फैसला 16-11-2017 को आया और दिसंबर 2017 में चुनाव परिणाम आने पर सरकार बदल गयी। इस फैसले पर अमल करने की जिम्मेदारी जय राम सरकार पर आ गयी। फैसले में सरकार को तीन माह के भीतर डवैल्पमैन्ट प्लान को अंतिम रुप से तैयार करने के निर्देश दिये गये थे।

We direct the State Government and/or its instrumentalities and more, particularly, the Town and Country Planning Department to finalize the Development Plan within three months from the date of pronouncement of this judgement without default. The Development Plan so finalized shall be notified in accordance with law. While finalizing the development plan, the directions and precautions stated in this judgement shall be duly considered by the concerned departments and the State of Himachal Pradesh.

लेकिन सरकार ने प्लान 2022 में तैयार की और जनता के सामने रखी। क्योंकि सरकार एन जी टी के फैसले के खिलाफ 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में चली गयी थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एन जी टी के फैसले को स्टे नहीं किया और परिणाम स्वरुप यह प्लान तैयार करना ही पड़ा। एन जी टी के फैसले को इस अधिनियम की धारा 15 के तहत अंतिम डिक्री का दर्जा हासिल है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ही धारा 33 के तहत बदलाव कर सकता है। एन जी टी के निर्देशों की अनुपालना न करना धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध है और धारा 28 के तहत अवहेलना करने वाले विभाग भी दंड के भागीदार बनते हैं। लेकिन सरकार ने कानून के इन पक्षों को नजरअंदाज करते हुये प्लान जारी कर दिया। इस पर फिर मामला एन जी टी में पहुंच गया। अब एन जी टी ने जिन शब्दों में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे सरकार और उसके तन्त्र की कानूनी समझ और अदालत के प्रति सरकार के सम्मान पर गंभीर सवाल उठते हैं।

As against above, the either in violation of law or on account of lack of knowledge, the authorities in the State of Himachal have made following statements in the draft plan showing irresponsible and illegal behaviour:

It is pointed out that the State of Himachal Pradesh trying to assume jurisdiction of Appellate Authority over the NGT, in breach of rule of law, not expected from a lawful Government which has to work as per law and the Constitution and not at its fancies as appears to be the case. Chief Secretary should be personally held liable for prosecution for such patent illegal acts of the State authorities.

चंबा को हेरिटेज टाउन के रूप में बनाया जाएगा:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंबा को हेरिटेज टाउन के रूप में बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि दुनिया

भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और यह कदम आय बढ़ाने का साधन बन जाए।

उन्होंने कहा कि चंबा में हेरिटेज भवनों की पहचान कर हेरिटेज वॉक की शुरुआत की जा सकती है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक इस खूबसूरत जगह की यात्रा कर सके।

उन्होंने यहां अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चंबा की कला, शिल्प और संस्कृति को विश्व स्तर पर ले जाने का वादा किया।

चंबा के चौगान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और युवा प्रोत्साहन पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने पहले ही इसे एक आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है और आने वाले वर्षो में यह देश के विकसित जिलों में से बहुत आगे होगा।

उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारों द्वारा राज्य और यहां चंबा में शुरू किए गए समग्र विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाले कुछ वर्षो में राज्य में कोई भी कच्चा घर नहीं रहेगा। उन्होंने 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और पेयजल सुविधा, सड़क संपर्क आदि सहित कई विकास परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया।

उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान स्टार्टअप शुरू करने और आपदा को अवसर में बदलने के लिए देश के युवाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे 100 से ज्यादा स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न कंपनी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी युवा शक्ति से प्रधानमंत्री एक नया भारत बनाना चाहते है।

अनुराग ठाकुर, जिनके पास खेल और युवा मामलों के मंत्री का प्रभार भी है, ने चंबा के सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में पांच इनडोर स्टेडियमों के अलावा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 मल्टी-व्यायामशालाओं के निर्माण की घोषणा की, ताकि युवा खुद को एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। इस मौके पर उन्होंने स्पोर्ट्स किट भी बांटी।

कार्यक्रम के दौरान, उन्होने कार्यक्रम स्थल पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा स्थापित सभी स्टालों का दौरा किया और जिला प्रशासन को होटलों में विशेष काउंटर विकसित करने के लिए कहा जहां ये समूह अपने उत्पादों को पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए आसान उपलब्धता के लिए रख सकें।

इससे पहले, उन्होंने एसएचजी, जैविक कृषि उत्पाद बनाने वाले संघ, उनके द्वारा लॉन्च किए गए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के थीम गीत से जुड़े कलाकारों और अन्य लोगों को सम्मानित किया।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रेम, करूणा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति भगवान बुद्ध ने पीड़ित मानवता को मध्यम मार्ग दिखाकर एक नई अवधारणा दी।

राज्यपाल ने कहा कि सर्वकल्याण और सहिष्णु समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हम भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने व्यवहार में शामिल करें।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा एक पवित्र त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके माध्यम से हम सभी को यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने पीड़ित मानवता की सेवा को अपना ध्येय बनाया। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मनुष्य को पीड़ा और कठिनाइयों से निकालकर शांतिप्रिय जीवन की ओर ले जाती हैं।

भारतीय डाक विभाग सुकन्या समृधि योजना से कर रहा बेटियों का भविष्य उज्जवल

शिमला/शैल। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के अंतर्गत वर्ष 2015 से बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृधि योजना की शुरुआत की गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना का मुख्य लक्ष्य बेटियों के अभिवावकों को बेटियों के उज्जवल व सुरक्षित भविष्य के लिए उच्चतर व्याज दर के साथ-साथ एक लोकप्रिय निवेश विकल्प उपलब्ध करवाना है।

सुरेन्द्र पाल शर्मा, अधीक्षक डाकघर धर्मशाला द्वारा सुकन्या समृधि योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना के माध्यम से लाभार्थी द्वारा निवेश करके एकमुश्त राशि बेटी की शिक्षा या फिर शादी के लिए प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होगा। इस अकाउंट में निवेश की न्यूनतम सीमा 250 रुपए है तथा अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए हैं। यह निवेश बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर वर्तमान में 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में छूट भी प्रदान की जाती है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लांच किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट किसी भी डाकघर की शाखा में खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन बेटी की आयु 21 वर्ष की होने या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने तक किया जा सकता है। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 50% की रकम की निकासी की जा सकती है। इस योजना में डाकघर द्वारा डिजिटल माध्यम से रकम जमा करवाने की भी सुविधा दी जा रही है।

सुरेन्द्र पाल शर्मा द्वारा बताया गया कि इस योजना के आरम्भ से अब तक धर्मशाला डाक मण्डल में लगभग 49876 खाते खोले जा चुके है। धर्मशाला डाक मण्डल में चालू माह (मई-2022) को सुकन्या समृधि माह के रूप में मनाया जा रहा है जिसका मुख्य लक्ष्य प्रत्येक डाकघर स्तर पर विशेष अभियान चला कर इस योजना से बंचित पात्र बालिकाओ के सुकन्या समृधि खाते खोल कर उन्हें इस हितकारी योजना से जोड़ना है। इस योजना से जुड़ने के लिए बेटी के माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के द्वारा बेटी के जन्म से 10 साल का होने तक खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है तथा खाता खुलवा आते समय बेटी का जन्म प्रमाण पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा । इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण भी जमा करना होगा।

योजना और प्रपत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी https://india post.gov.in पर उपलब्ध है। इन योजनाओ की अधिक जानकारी के लिए अधीक्षक डाकघर, धर्मशाला कार्यालय के दूरभाष नंबर: - 01892 - 228170 पर भी संपर्क किया जा सकता है

कृषि विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। कृषि विभाग द्वारा अपनी विविध गतिविधियों के

बारे में राज्य कृषि प्रबन्धन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि सचिव राकेश कंवर ने की।

इस अवसर पर कृषि सचिव ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती व कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले व अन्य कार्यक्रमों में स्टाल इत्यादि लगाकर विभाग की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं में आपसी संवाद के माध्यम से बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं।

उन्होंने अधिकारियों को विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारियों को अपने अनुभवों के आधार पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए।

निदेशक कृषि डॉ. नरेन्द्र कुमार धीमान ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई विभिन्न तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए नवोन्मेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विभाग की विभिन्न योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।

इस अवसर पर विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला के प्रतिभागियों ने आपसी संवाद किया तथा अपने सुझाव भी दिए। कार्यशाला में विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पण्डित सुख राम के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पण्डित सुख राम के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि पण्डित सुख राम का दूरसंचार क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वह एक वरिष्ठ नेता थे जिनका हिमाचल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिसे प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे।

राज्यपाल ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

पंडित सुख राम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुख राम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ हनुमानघाट मंडी में अंतिम संस्कार किया गया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ.राम लाल मारकंडा, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक राकेश जमवाल, इंदर सिंह गांधी और जवाहर ठाकुर, कई भाजपा नेता और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हजारों लोगों ने पंडित सुख राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सेरी मंच मंडी में रखा गया था। ब्रेन स्ट्रोक के उपरान्त एम्स नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुख राम को देश में दूरसंचार क्रांति लाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए हमेशा तत्पर पंडित सुख राम के रूप में देश और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश ने एक महान नेता खो दिया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पंडित सुख राम ने अपने साठ वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास और यहां के लोगों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके योगदान के लिए राज्य की जनता उन्हें हमेशा याद रखेगी।

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल का महा क्विज प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने माइगव हिमाचल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जन भागीदारी से सुशासन, हिमाचल का महा क्विज प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसी

उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से मेगा क्विज का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रश्नोत्तरी केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित होगी और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तरी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने में बहुत सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रश्नोत्तरी राज्य सरकार के माइगव हिमाचल वेब पोर्टल पर आयोजित की जा रही है। इस तरह की प्रतियोगिता राज्य में पहली बार आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन के बारे में जागरूक करना है। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आम जनता सरकार की योजनाओं के बारे में जान सकेगी और उनके लिए इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना और सुगम हो जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कई बार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी के अभाव में लोग विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई नई पहल की हैं और प्रश्नोत्तरी से लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने गरीबों और दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि बेटी है अनमोल, शगुन योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आदि जैसी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वरदान साबित हुई हैं।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विभिन्न विषयों पर कुल आठ राउंड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहला क्विज महिला सशक्तिकरण पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि क्विज के प्रत्येक राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आठ राउंड पूरे करने के बाद विजेता को 51 हजार रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 21 हजार रुपये और तीसरा स्थान हासिल करने वाले को 11 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सभी प्रतिभागियों को ऑटो जेनरेटेड डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

सीईओ माइगव, भारत सरकार अभिषेक सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रूपाली ठाकुर, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन, सीईओ माइगव हिमाचल राजीव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भेंट की।

इस अवसर पर धर्मशाला में जून

माह में प्रस्तावित सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अधिवेशन के आयोजन के बारे में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दो दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से विशेष तौर पर हिमाचल आने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे तथा राष्ट्र स्तरीय अधिवेशन के सफल आयोजन के बारे में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी नीति आयोग के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने पर्यटन विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा, रोपवे कनेक्टिविटी, विद्युत वाहन और सतत विकास की दिशा में कई अभिनव पहल की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजना के माध्यम से हिमाचल पर्यटन तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए बेहतर संपर्क स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत वाहन नीति तैयार कर प्रदेश इलेक्ट्रिक व क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल टूरिज्म, हवाई संपर्क को और बेहतर करने तथा प्रदेश के सतत विकास में नीति आयोग से सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया।

मतदाता सूचियों के अपडेट का कार्यक्रम जारी

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों को छोड़ कर अन्य शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के अद्यतनीकरण (अपडेट) का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि जिला स्तर द्वारा मतदान केन्द्र की मैपिंग पूरी करने की तिथि 12 मई, 2022 निर्धारित की गई है। खण्ड स्तर द्वारा अनुभाग की मैपिंग 17 मई, 2022 तक, मतदाता सूची भाग-1 का सत्यापन और मतदाता सूची भाग-2 के निर्वाचकों की मैपिंग 28 मई, 2022 तक तथा भाग-1 व भाग-2 का एकीकरण 31 मई, 2022 तक पूरा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 31 मई, 2022 के बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके उपरान्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी करेगा।

राशन कार्ड धारक प्रदेश में 15 जून, 2022 तक करवाएं ई-केवाईसी

शिमला/शैल। राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा राशन कार्ड सही करने के लिए राशन कार्ड डाटा का मिलान आधार कार्ड के डाटा से किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया को ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर) अथवा अपने ग्राहक को जाने व पहचाने नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2019 में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे, परन्तु कोविड-19 के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका और स्थिति सामान्य होने के कारण अब इसे किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने शत-प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि टीपीडीएस कन्ट्रोल ऑर्डर-2015 के अनुसार राज्य सरकारों को लाभार्थियों की सूची का मूल्यांकन करना अनिवार्य है ताकि अनुचित परिवारों एवं लाभार्थियों को डाटाबेस से हटाया जा सके और सही लाभार्थियों का विवरण आधार में दर्ज विवरण के अनुरूप हो सके। इससे लाभार्थी राशनकार्ड डाटा का अन्य योजनाओं में भी सुगमतापूर्वक उपयोग कर सकेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि ई-केवाईसी एक साधारण प्रक्रिया है और उपभोक्ता राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान में जाएगा तो उसकी ई-केवाईसी उसी समय उचित मूल्य दुकानधारक द्वारा कर दी जाएगी। एक सदस्य की ई-केवाईसी में आधा मिनट का समय भी नहीं लगता है। ई-केवाईसी करवाना प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अति आवश्यक है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा अथवा उचित मूल्य दुकानधारक गांवों में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक सफल ई-केवाईसी के लिए उचित मूल्य की दुकान के संचालक को चार रुपये प्रति प्रविष्टि पारिश्रमिक के रुप में दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या होना अनिवार्य है। विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर ई-केवाईसी के लिए सभी उचित मूल्य दुकानधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस बारे सभी जिला पंचायत अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों एवं पंचायत सचिवों व सहायकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि यदि ई-केवाईसी की प्रक्रिया उचित मूल्य की दुकान पर पूर्ण हो जाती है तो उपभोक्ताओं को आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है। यदि किसी कारणवश ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण विफल रहता है तो उपभोक्ता अगले दिन ई-केवाईसी के लिए प्रयास कर सकता है। यदि फिर भी ई-केवाईसी नहीं होता है तो उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव या सहायक तथा शहरी क्षेत्र में निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति के कार्यालय में अपनी आधार संख्या या राशन कार्ड के साथ जाना होगा। यदि आधार संख्या गलत है तो राशन कार्ड डाटाबेस में आधार संख्या ठीक करनी होगी।

यदि आधार संख्या सही है फिर भी ई-केवाईसी नहीं लग रही हो तो आधार में ई-केवाईसी अपडेट करवाने होंगे। विभाग ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समस्त परिवार सहित अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को 15 जून, 2022 तक पूर्ण करवाएं। इसके अतिरिक्त जो उपभोक्ता नौकरी, पढ़ाई इत्यादि के कारण प्रदेश के अन्य स्थानों पर निवास कर रहे हैं, वे उनके समीप की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि उपभोक्ता किसी कारणवश प्रदेश से बाहर हैं, वे प्रदेश वापसी पर ई-केवाईसी करवाने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में समीप की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा लें।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 के माध्यम से 22539 शिकायतों का निवारण

शिमला/शैल। पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने जानकरी दी कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 के माध्यम से प्रदेश में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 पर आज तक 23978 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं, जिनमें से 22539 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शेष 1439 शिकायतों को हल करने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश वही शिकायतें लम्बित है, जिनमें शिकायतकर्ता कार्रवाई की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि 1100 पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों को निर्धारित समयावधि में निपटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1100 पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों का नामित नोडल अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि आम लोगों की समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जा सके।

विधानसभा परिसर धर्मशाला घटना पर त्वरित कार्रवाई की गईः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला प्रवास के दौरान परिधि गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुये कहा कि विधानसभा परिसर धर्मशाला के द्वार पर खालिस्तानी झण्डे लगाने और दीवार पर नारे अंकित करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कारवाई की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस गैर कानूनी घटना में शामिल एक आरोपी को तीन दिन के भीतर गिरफ्तार किया है। पुलिस एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयासरत है, जोकि फरार हो गया था।

पुलिस भर्ती पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी गहन जांच जारी है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

तुम्हे अन्दर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हे पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हे आध्यात्मिक नहीं बना सकता तुम्हारी आत्मा के आलावा कोई और गुरु नहीं है।.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

चिंतन के बाद कांग्रेस से अपेक्षाएं

बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ ब्याज दरों तथा ई एम आई का बढ़ना और शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का पलायन कुछ ऐसे संकेत है जिनसे यह लगने लगा है कि कहीं भारत के हालात भी पड़ोसी देश श्रीलंका जैसे तो नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि इस सब के कारण विदेशी मुद्रा भंडार का संतुलन भी बिगड़ गया है। अर्थ शासन के सारे विकल्प गड़बड़ा चुके हैं। आने वाले दिनों में कारपोरेट सैक्टर को या तो 15 से 20% तक नौकरियों में या वेतन में कटौती करनी पड़ेगी। यह वह हालात है जिनमें से देश की बहुसंख्या को गुजरना ही पड़ेगा। चाहे वह सरकार की नीतियों के जितने भी समर्थक रहे हों। देश इस दिशा में क्यों पहुंचा है इस पर कभी खुली बहस नहीं हो पायी है। बैंकों का एनपीए क्यों बढ़ता गया? कर्जदार कर्ज लेकर देश से बाहर कैसे चले गये? कंपनियों को दिवालिया होने की सुविधा देते हुये उनके संचालकों को व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से क्यों मुक्त रखा गया? बैंकों का कितना एनपीए राइट ऑफ करके उस घाटे को आम आदमी के जमा पर ब्याज दरें घटाकर पूरा करने का प्रयास किया गया। कैसे जीरो बैलेंस के खातों में न्यूनतम निवेश की शर्त डाली गयी? नोटबंदी से जब उद्योग प्रभावित हुये तब उनको उबारने के लिये कर्ज की शक्ल में आर्थिक पैकेज देने के बावजूद वह संकट से बाहर क्यों नहीं आ पाये? कोरोना में आये लॉकडाउन से उत्पादन को प्रभावित होने से क्यों नहीं बचाया जा सका? जब यह सब घट रहा था तब देश में हिंदू–मुस्लिम, मंदिर–मस्जिद, गाय, लव जिहाद, तीन तलाक और धारा 370 जैसे मुद्दों पर जनता को व्यस्त रखा गया। अधिकांश मीडिया भी सरकार की अंधभक्ति में व्यस्त हो गया। असहमति जताने वाले हर स्वर को दबाने कुचलने के लिये देशद्रोह झेलने का डर दिखाया गया। हर चुनाव में ईवीएम पर खड़े सवालों को आज तक नजरअंदाज किया गया। चुनावी रणनीतिकार राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के सूत्र तो सुझाते रहे लेकिन समाज इस संकट से कैसे बाहर निकले यह आज तक उनके लिये मुद्दा नहीं बन पाया है। जबकि राजनीतिक दलों के लिये यह पहला मुद्दा होना चाहिये था। क्योंकि राजनीतिक दलों की ही यह पहली जिम्मेदारी है। जब राजनीतिक दल यह जिम्मेदारी निभाने में असफल हो जायेंगे तब यहां भी श्रीलंका की तरह जनता सड़कों पर उतरने को विवश हो जायेगी। यह याद रखना होगा कि श्रीलंका में 2017 में धार्मिक और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रताड़ना का चलन शुरू हुआ था। जो आज जनक्रांति बनकर सामने आया है। इस समय यह चर्चा उठाना इसलिये आवश्यक है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अभी तीन दिन का चिंतन मन्यन करके लौटी है। इस चिंतन में अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता व्यक्त की गयी है। उनमें विश्वास जगाने के लिए कुछ क्रियात्मक कदम उठाने की बात की गई है इसी के साथ कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा ने कांग्रेस जनों से कुछ त्याग करने की मांग भी की है। यह कहा गया कि पार्टी ने उन्हें जो कुछ दिया है उसे अब लौटाने की आवश्यकता है। यह स्वीकारा गया है कि इस समय देश असाधारण परिस्थितियों से गुजर रहा है जिनमें कठिन फैसले लेने आवश्यक होंगे। त्याग की मांग पर कितने नेता अमल कर पाते हैं और कितने इसी के कारण पार्टी से बाहर भी चले जाते हैं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा है वह बढ़ते आर्थिक असंतुलन का है जिसमें कुछ लोगों की संपत्ति तो इस संकट काल में भी कई गुना बढ़ गयी है और अधिकांश साधनहीन होता जा रहा है। आम आदमी के पेट के लिये जब व्यवस्था संकट खड़ा कर देती है तब वह व्यवस्था की नीयत और नीति के जागरूक होने का प्रयास करता है। आज व्यवस्था की नीयत और नीति के हर पहलु पर आम आदमी को जानकार तथा जागरूक करने की आवश्यकता है। 2014 में जिस भ्रष्टाचार का सरकार को पर्याय प्रचारित कर सत्ता परिवर्तन हुआ था उस पर आज क्या स्थिति है यह सवाल पूछने का साहस हर आदमी में जगाने की आवश्यकता है। आज सत्तारूढ़ दल के वैचारिक आधारों पर बहस उठाने की जरूरत है। यह समझाने की आवश्यकता है कि चयन के स्थान पर मनोनयन परिवारवाद से ज्यादा घातक होता है। यह धारणा हिलानी होगी कि केवल संभ्रान्त को ही शासन का अधिकार है। प्राकृतिक संसाधनों की स्वायत्तता के खतरों पर खुली बहस आयोजित करने की जरूरत है। क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लिये संघ स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद इन धारणाओं के लिये वैचारिक धरातल तैयार करने में लगा रहा है। जिसके परिणाम इस तरह से सामने आ रहे हैं। आज हर राजनीतिक दल के लिये इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिये कांग्रेस की जिम्मेदारी सबसे बड़ी हो जाती है।

शांति और सहिष्णुता के पर्याय महात्मा बुद्ध

जी. किशन रेड्डी
भारत सरकार के संस्कृति,पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

गौतम बुद्ध किस महापुरुष का नाम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, उनको ज्ञान बोध भी पूर्णिमा के दिन हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा के ही दिन हुआ। ऐसा अद्भुत संयोग किसी महामानव के ही जीवन में आता है। भारत जैसे धार्मिक देश में पूर्णिमा का दिन आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है और प्रकाश का प्रतीक है।

मानव के मन में प्रश्नों का जन्म होना स्वभाविक है। सामान्य लोग उन प्रश्नों का अपने अंदर ही अंत कर देते हैं और कुछ विशेष लोग उन प्रश्नों के उत्तर के लिए ललाहित हो, सब कुछ त्याग कर उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। वही लोग मानव से महामानव और महापुरुष बनते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के मन में हुआ।

उनके परिवार के लोगों को किसी संत ने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा होकर या तो यशस्वी राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत बनेगा। परिवार के लोग डर गए, और उन्होंने उनको बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रखवा। लेकिन एक दिन वो घर से बाहर निकले और उन्होंने 3 दृश्य देखे, पहला– एक अत्यंत बीमार व्यक्ति, दूसरा–बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति और तीसरा– एक मृत व्यक्ति, उनके मन में आया कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। इन तीन प्रश्नों ने उन्हे बहुत विचलित कर दिया। फिर वो राजपाठ, राजमहल, पत्नी और परिवार को त्याग कर इन प्रश्नों की खोज में निकल पड़े। उन्होंने एक सन्यासी को देखा और मन ही मन सन्यास ग्रहण करने की ठान ली। बस वहीं से राजकुमार सिद्धार्थ की महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। महात्मा बुद्ध ने बिना अन्न, जल ग्रहण किए करीब 6 साल घोर तपस्या की, उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान बौध हुआ। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों वर्षो से इस धरा को प्रकाशमान कर रहा है।

महात्मा बुद्ध इस धरती पर एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। जिन्होंने बौद्ध धर्म कि स्थापना कर दुनिया को शांति, करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए आज विश्व के अनेक देश बौद्ध धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। वर्तमान समय में जब विश्व अशान्ति, आतंकवाद, अनैतिकता और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो भगवान गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन हमें समाधान का मार्ग दे सकता है। उन्होंने मनुष्य को अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, धैर्य, संतोष और नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। पंचशील का उनका सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकता है, जिसमें उन्होंने कहा हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना शामिल हैं। इस बात पर उनका विशेष बल रहा कि जीवन में प्रकृति का सम्मान सर्वोपरि है।

नरेंद्र मोदी सरकार भगवान बुद्ध के उपदेशों, संदेशों और विचारों को दुनिया में जन–जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बुद्ध पूर्णिमा को राष्ट्रीय उत्सव के रूप मे मनाने का निर्णय किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस उत्सव को बढ़ावा दिया।

उनके द्वारा दिया गया ज्ञान विश्व के लिए शांति और एकता की शक्ति बन सकता हैं। विगत वर्ष बुद्ध पूर्णिमा विश्व शांति और कोरोना महामारी से राहत के लिए समर्पित थी। दुनिया जब मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उस समय भारत के साथ एकजुट होकर बोधगया–भारत, लुंबिनी–नेपाल, कैंडी–श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान के प्रमुख बौद्ध मंदिरों में विश्व शांति के लिए एक साथ प्रार्थनाएँ आयोजित की गई। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध सार्वभौमिक हैं क्योंकि वो अपने भीतर से शरुआत करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है, तो वह दुनिया को भी प्रकाश देता है। इसलिए बुद्ध दर्शन में ''अप्प दीपो भव'' भारत के आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है।

बौद्ध धर्म को दुनिया के चार बड़े धर्मो में से एक माना जाता है। दुनिया में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और उनमें से 90% दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में रहते हैं। इसके बाद भी, यह अनुमान है कि हर साल 0.005% से कम बौद्ध तीर्थयात्री यात्रा के लिए भारत आते हैं। चूंकी बौद्ध विरासत भारत में सर्वाधिक है, इसलिए भारत की आजादी के 75 वर्षो में हमारा संकल्प अधिकाधिक बौद्ध तीर्थ यात्रियों को भारत दर्शन कराना है और इस दिशा में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय काम कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध सर्किट बनाया तथा बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। जिसमें सांची–सतना–रीवा–मंदसौर–धार का विकास, श्रावस्ती–कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास, बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, जूनागढ़– गिर सोमनाथ–भरूच–कच्छ– भावनगर – राजकोट– मेहसाणा का विकास तथा आंध्र प्रदेश के शालिहुंडम–थोटलाकोंडा– बाविकोंडा–बोज्जानकोंडा– अमरावती– अनुपु में बौद्ध सर्किट का विकास हुआ है। भगवान बुद्ध के जीवन का संबंध जिन राज्यों से रहा बौद्ध सर्किट में उन्हे जोड़ा गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। बौद्ध सर्किट विकास में कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, सांस्कृतिक अनुसंधान, विरासत और शिक्षा, जन जागरण, संचार और एक्सेस को शामिल किया है। दुनिया भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों को यात्रा में आसानी हो इसके लिए भारत सरकार ने कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में लगभग 260 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। साथ ही बौद्ध सर्किट में आईआरसीटीसी द्वारा ''बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस'' स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है। पर्यटन मंत्रालय, विकास क्षमता बढ़ाने पर भी निरंतर कार्यरत है, इस दिशा में हमने थाई, जापानी, वियतनामी और चीनी भाषाओं में भाषाई पर्यटक सूत्रधार प्रशिक्षण को शामिल किया है। वर्ष 2018 और 2020 के बीच 525 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और वर्ष 2020 से 2023 के बीच 600 अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे विशेष रूप से विदेश से आने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों को भाषाई कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी। देश के कई विशिष्ट संस्थानों में बौद्ध धर्म से संबंधित पाठयक्रमों को पढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में अमेरिका का दौरा किया, उस समय 157 कलाकृतियाँ और पुरावशेष को भारत वापस लाया गया था। जिसमें 16 कलाकृतियाँ और पुरावशेष बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भगवान गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन को आधार मानकर वैश्विक शांति, बंधुत्व और सहिष्णुता के प्रति अपनी जबाबदारी सुनिश्चित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन को आत्मसात कर, हम एक नए भारत और अतुल्य भारत का निर्माण करने में सफल होंगे।

भारत:नीति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

स्मृति इरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

भारत सरकार ने पिछले एक दशक में सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय (सभी के कल्याण के लिए, सभी की खुशी के लिए) की उक्ति को एक स्पष्ट वास्तविकता में बदल दिया है। जनहित (सार्वजनिक हित) के प्रचलित सार को (मुख्यधारा) के लिंग आधारित अनुभवों के नए आयामों से जोड़ा गया है। देश की विभिन्न नीतियों और इनके कार्यान्वयन के माध्यम से लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि यह कृत्रिम रूप से शामिल की जाने वाली एक अप्रभावी प्रक्रिया बनकर न रह जाए।

वर्त्तमान सरकार नीतिगत कार्यान्वयन के लिए प्रणाली – आधारित लैंगिक दृष्टिकोण अपनाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए महिलाओं को अनिवार्य रूप से घर के मुखिया के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभ – क्रमश: गृह – स्वामित्व और एलपीजी कनेक्शन – महिला लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। इस तरह के कदमों से महिलाओं की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच स्पष्ट रूप से आसान हुई है एवं अन्य बातों के साथ – साथ उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हुई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जैसी पुरानी योजनाओं में, जिनके तहत महिलाओं को अनजाने में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा से अलग रखा गया था, बदलाव किये गए और आवश्यक होने पर इन्हें वापस ले लिया गया। इसके स्थान पर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम – जेएवाई) न केवल उन परिवारों को योजना के लिए पात्र बनाती है, जहाँ कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं हैं, बल्कि यह प्रति परिवार 5 – लाभार्थी की अर्थहीन सीमा को भी समाप्त करती है, जिसके तहत बड़े परिवारों में पुरुष वरीयता के कारण महिलाओं को इस सुविधा से वंचित रखा जाता था। इसके अलावा, पीएम – जेएवाई पर्याप्त संख्या में ऐसे स्वास्थ्य लाभ पैकेजों का समर्थन करता है, जो या तो प्रकृति के अनुसार महिला – केंद्रित हैं या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लागू हैं। योजना के अंतर्गत, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने कैंसर चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया है।

मुश्किल से एक दशक पुरानी सरकार ऐसे कार्य कर रही है, जिन्हें सदी के बड़े हिस्से के दौरान राष्ट्र के शासन को संभालने वाले अन्य सत्ताधारी नहीं कर पाए (यह महिलाओं को केंद्र में रखकर दूरदृष्टि का निर्माण करना है) (यह नारी शक्ति का पोषण करना है।) महिलाओं को आवास और एलपीजी जैसी परिसंपत्ति देकर, असमानता पर आधारित यथास्थिति को चुनौती दी जा रही है। न केवल नीतियों के माध्यम से, बल्कि लिंग आधारित अंतर को कम करते हुए भी ऐसा किया जा रहा है।

मौजूदा सरकार के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2019 में पहला राष्ट्रव्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण किया गया था। समय उपयोग सर्वेक्षण ने अंतत: महिलाओं के अवैतनिक व कठिन परिश्रम, जिसे अक्सर मान्यता नहीं दी जाती है, के लिए एक संख्या को सामने रखा – एक दिन में 7.2 घंटे, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय पुरुष के औसत 2.8 घंटे के मुकाबले भारतीय महिला औसत देखभाल और घरेलू सेवाओं के लिए कितना अधिक समर्पित है। इसके प्रभावों की जांच और परिणामस्वरुप नीतिगत सुधार इस सर्वेक्षण द्वारा ही संभव हुए हैं। उल्लेखनीय है कि 1998 में, दूरदर्शी अटलजी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में, टीयूएस को पहली बार 6 भारतीय राज्यों में पायलट आधार पर संचालित किया गया था। अब, समय उपयोग सर्वेक्षणों को नीतिगत चर्चा में एक प्रमुख स्थान मिल गया है और संयुक्त राष्ट्र – सतत विकास लक्ष्यों (यूएन – एसडीजी) की वैश्विक संकेतक रूपरेखा में इनका उल्लेख मिलता है।

पोषण, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, प्रजनन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर महत्वपूर्ण जानकारी के नियमित स्रोत के रूप में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) समान स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने में, विशेष रूप से महिलाओं के सन्दर्भ में, भारत के प्रदर्शन का एक पैमाना बन गया है। एनएफएचएस – 4 (2015 – 16) की प्रतिदर्श निर्धारण रणनीति, राष्ट्र के सभी जिलों के लिए एक व्यापक, पद्धति केन्द्रित नवीकरण तथा सांख्यिकीय लेखांकन पर आधारित है, जो अपने पूर्ववर्ती एनएफएचएस – 3 (2005 – 06) के राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिदर्श की तुलना में एक बड़ा सुधार सिद्ध हुई है। उप – राष्ट्रीय और जिला – स्तरीय डेटा को दर्शाने से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राथमिकता वाले व लक्षित हस्तक्षेपों को दिशा मिलती है।

एनएफएचएस – 4 में पहली बार लिंग – आधारित कैंसर की व्यापकता दर्ज की गई। एनएफएचएस – 5 में पहली बार इस बारे में जानकारी दर्ज की गयी कि क्या महिलाओं का कभी मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण हुआ है। साथ में, एनएफएचएस – 4 और 5 (भारतीय महिला के स्वास्थ्य पर एक व्यापक सामान्य सर्वेक्षण प्रदान करते हैं) और डेटा के एक अतुलनीय भण्डार के रूप में कार्य करते हैं।

महिलाओं को शामिल करने के लिए राष्ट्र की सांख्यिकीय संरचना को फिर से तैयार किया गया है। लोकप्रिय अकादमिक कथन है कि 'जो गिना जाता है, वही महत्वपूर्ण है' और यह नीति – निर्माण की प्रक्रिया में संसाधन आवंटन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इसे स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा एकत्र किए गए पंचवर्षीय रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को त्रैमासिक और वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया (ताकि श्रम बल के आंकड़ों को लिंग के आधार पर अलग – अलग किया जा सके।) पीएलएफएस अब महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात, महिला श्रम बल भागीदारी दर और महिला बेरोजगारी दर जैसे लिंग – पृथक डेटा प्रदर्शित करता है।

गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2014 से कन्या भ्रूण हत्या पर डेटा का संग्रह शुरू किया। इस तरह के निराशाजनक डेटा को स्वीकार करना बहुत कठिन है, लेकिन डेटा के आधार पर स्थिति की सही जानकारी के लिए, मौजूदा सरकार ने इनका संग्रह करने की सुविधा प्रदान की है और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के माध्यम से इसके प्रभावों पर तेजी से काम किया है।

डेटा के आधार पर स्थिति की सही जानकारी को समाधान और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। सरकार या तो कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों के माध्यम से या सर्वेक्षणों के माध्यम से लिंग – पृथक डेटा संग्रह कर रही है और योजनाओं को तैयार करने या उनमें सुधार करने के लिए इनका उपयोग कर रही है। इस प्रकार एक क्षेत्र में हुए सुधार अन्य क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अब अकादमिक, अनुसंधान और मूल्यांकन परामर्शदाता से जुड़े व्यक्तियों और समूहों का यह दायित्व है कि वे ऐसे डेटा का परीक्षण (ऑडिट) करें और तीसरे पक्ष के आकलन का संचालन करें तथा जनहित के लिए सार्वजनिक नीति में लैंगिक – आधार को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य संस्थानों में अधोसंरचना सुधार से मरीजों को मिल रहीं बेहतर सेवाएं

लोगों को घर – द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सर्वोच्च प्राथमितकता के साथ कार्य करत हुए प्रदेश सरकार ने जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य संस्थान खोलने को अधिमान दिया है वहीं स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए भी विशेषतौर पर प्रयास किए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों और पेरा – मेडिकल स्टाफ के खाली पड़े पदों को भरने के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। इन संस्थानों में बेहतर जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक मशीनों और उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

दूर – दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं घर – द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष प्रत्येक स्वास्थ्य खण्ड में मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकसित किया जाएगा। मरीजों की सुविधा के लिए 50 नई एम्बुलेंस खरीदने का भी निर्णय लिया गया है।

आईजीएमसी, शिमला में 103. 18 करोड़ रुपये लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया गया है। इस भवन के निर्माण कार्य पर 73 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में उपलब्ध करवाई गई। इस अस्पताल में ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है जिसके आरम्भ होने से आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को उपचार की बेहतर सुविधा प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध होगी।

कोविड महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अधोसंरचना को मज़बूती प्रदान की है ताकि भविष्य में किसी महामारी की स्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। आज प्रदेश में 48 ऑक्सीजन संयंत्रों, 1000 से अधिक वेंटिलेटर्स की सुविधा उपलब्ध है। उप – स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक 5000 से अधिक ऑक्सीजन कंसट्रेटर उपलब्ध हैं तथा 10 हजार से अधिक ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता सृजित की गई है।

प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए 33 नए उप – स्वास्थ्य केंद्र, 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आठ स्वास्थ्य उप – केंद्र खोले हैं। वहीं, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न अस्पतालों में बिसतरों की क्षमता बढ़ाई गई है और कई स्थानों पर नए शिक्षण संस्थान खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है।

वर्तमान राज्य सरकार ने 1654 चिकित्सा अधिकारियों, 975 स्टाफ नर्सों, 76 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, 199 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, 194 प्रयोगशाला सहायकों, 35 ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट, 462 फार्मासिस्ट, 111 रेडियोग्राफर, 11 ऑपथेल्मिक अधिकारियों के पदों को भरा है।

प्रदेश सरकार ने इस वर्ष चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद भरने का फैसला लिया है। इसके अलावा, आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरे जाएंगे जिनमें से 100 पद सीधी भर्ती और शेष बैचवार आधार पर भरे जाएंगे। आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया है। इनमें से 52 पद सीधी भर्ती और 48 बैचवार भरे जाएंगे।

पिछले चार वर्षों में 10 आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और तीन आयुर्वेद अस्पतालों को स्तरोन्नत किया गया है। कांगड़ा जिले के पपरोला में 8.37 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सैंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर जेरीएट्रिक हैल्थ का शुभारम्भ किया जा चुका है।

केंद्र सरकार के सहयोग से बिलासुपर में एम्स और ऊना में पीजीआई के सेटेलाइट सेंटर और तीन मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिली है। भारत सरकार ने प्रदेश के लिए एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किया है जिसका कार्य इस वर्ष नालागढ़ में आरंभ हो जाएगा। इस पार्क से प्रदेश में 5 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा।

प्रदेश सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक तकनीकों की सुविधा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है। डा. वाई.एस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन में वायरोलॉजी लैब, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और एमजीएमएस संयंत्र को कार्यशील बनाया गया है। आईजीएमसी, शिमला में किडनी ट्रांस्पलांट की सुविधा आरंभ की गई है।

सीपुर में आयुर्वेद औषधालय तथा कनहोला में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला शिमला के मशोबरा के समीप सीपुर में जिला स्तरीय सीपुर मेले के समापन समारोह के अवसर पर विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए सीपुर में आयुर्वेद औषधालय तथा कनहोला में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने मशोबरा-

सीतापुर-देवठी सड़क की मेटलिंग व टारिंग करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं की भूमि है तथा लोग स्थानीय देवी-देवताओं पर बहुत विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग वर्षभर इन स्थानीय देवी-देवताओं के सम्मान में मेले व उत्सव मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेले व उत्सव प्रदेश की विविध सांस्कृतिक समृद्धता का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि उत्सव समाज की भावनात्मक तथा सामाजिक एकता को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति व परम्पराओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वह समाज ही उन्नति व खुशहाली प्राप्त करता हैं, जो अपनी परम्पराओं व संस्कृति का सम्मान करता हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी परम्पराओं पर भी गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपने दौरे के दौरान देश की समृद्ध संस्कृति व परम्पराओं को बढ़ावा देना सुनिश्चित करते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने लगभग साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान यह सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकार की सभी नीतियां, कार्यक्रम तथा योजनाएं समाज के संवेदनशील वर्गो के कल्याण व उत्थान पर केन्द्रित हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुगन योजना के तहत प्रदेश के बीपीएल परिवारों की प्रत्येक कन्या को विवाह के समय शगुन के रूप में 31000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2.30 लाख परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश धुंआ मुक्त प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए सीपुर सड़क की शीघ्र मेटलिंग की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने घोषणा की है कि जल शक्ति विभाग के तहत आने वाली क्रैगनेनो-शुहल सड़क को उचित रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने ढली से शिरदू सड़क के रख-रखाव के लिए 8 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायत पधेची-भरांडी में खेल मैदान के निर्माण के लिए 7 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मशोबरा के नाम भूमि हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों को अपनी ऐच्छिक निधि से 21000 रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किए।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने क्षेत्र के लोगों को मेले की बधाई देते हुए कहा कि मेले एवं उत्सव सदियों से मनोरंजन का साधन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मेले एवं उत्सव लोगों को सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने के अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

ग्राम पंचायत मशोबरा की प्रधान गायत्री देवी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा क्षेत्र की विभिन्न मांगों की विस्तृत जानकारी भी दी।

सीपुर मेला समिति के संयोजक बालक राम ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का इस अवसर पर स्वागत किया। उन्होंने इस जिला स्तरीय मेले के समृद्ध ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला तथा मुख्यमंत्री से इस मेले को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने का भी आग्रह किया।

चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, पूर्व विधायक रूप दास कश्यप तथा भगतराम चौहान, क्षेत्र के भाजपा नेता विजय ज्योति सेन, कैलाश फेडरेशन तथा जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि मेहता, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी भी अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।

योग पद्धति को जन-जन तक पहुंचाएंगे भारत को स्वस्थ बनाएंगे:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। योग पद्धति को भारत के जन-जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। यह उद्गार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला के एचपीसीए के स्टेडियम में योगा महोत्सव का शुभारंभ करने के उपरांत प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 25 हजार जगहों पर योगा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। योग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम देशभर में आयोजित किए जाएंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर 21 जून को स्वेच्छा से देश का हर नागरिक योगाभ्यास के साथ जुड़ सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव तक योग को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने की पैरवी की थी और दुनिया के सभी देशों ने इसे स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है।

योग प्रकृति तथा मनुष्य के बीच का सामंजस्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रारंभिक दौर में भी भारत के आम जनमानस के लिए योग एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, लोगों ने योग तथा काढ़ा के साथ कोविड से अपने जीवन की रक्षा भी की है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है तथा सभी युवाओं को योग के प्रति प्रेरित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत तथा कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इससे पहले एनवाईएसएफ की ओर से रचित कौशिक ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए योगा महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ धर्मशाला में एनएसएस, खिलाड़ियों तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, नेहरू युवा केंद्रों के वालंटियर्स ने भी भाग लिया। दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से भी युवा योगाभ्यास में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक विशाल नैहरिया, जिलाधयक्ष चंद्रभूषण नाग, उपायुक्त डा. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक खुशाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'हिमाचल एनवायरो प्रश्नोत्तरी' प्रतियोगिता का आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रदेश में 'हिमाचल एनवायरो प्रश्नोत्तरी-2022' राज्य स्तरीय अन्तर विद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रदेश में पर्यावरण के सम्बन्ध में जागरूक करना है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन आई.टी.सी. निमाइल के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता के लिए bit.ly/himachalenviroquiz 2022 वेबसाइट बनाई गई है। उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के लिए 07 मई, 2022 से प्रदेश के सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र की उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आरम्भ हो गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पाठशालाओं को पंजीकरण करवाना होगा तथा ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकतम तीन टीमें भाग ले सकती हैं। प्रत्येक टीम में दो विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण की अन्तिम तिथि 17 मई, 2022 निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि bit.ly/register-enviroquiz2022 2022 लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़िला स्तरीय ऑनलाइन स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन 20 मई, 2022 को किया जाएगा। इसमें प्रत्येक टीम को 15 मिनट में 30 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रतियोगिता की शीर्ष 36 टीमें राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के फिज़िकल राउन्ड में भाग लेंगी। विश्व पर्यावरण दिवस-2022 के अवसर पर नेकसिस कन्सलटिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्विज़ मास्टर वेन्की श्रीनिवासन द्वारा शिमला में 05 जून, 2022 को राज्य स्तरीय क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

सदस्य सचिव ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और पर्यावरण के संरक्षक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से इस ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 4200 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की लगभग 8000 टीमों के भाग लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में आठवीं से 12वीं कक्षा के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के प्रतिभागियों तथा विजेताओं को प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिक्षा विभाग के सहयोग से 22 अप्रैल, 2022 को 'विश्व पृथ्वी दिवस' के अवसर पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के प्रति भी जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था।

केन्द्रीय मंत्री से बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एल. मांडविया से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर का कार्य इस वर्ष जुलाई माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा और प्रदेश सरकार इसे जनता को समर्पित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस महत्वकांक्षी परियोजना के शुभारम्भ के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ नेटवर्क है तथा एम्स के आरम्भ होने से यह वर्तमान स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं सुविधाओं के क्षेत्र में एक और मील पत्थर सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एशिया में सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में जाना जाता है तथा राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित होने से औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राज्य में कच्चे माल के उत्पादन से फार्मा उद्योग को भी संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे फार्मा उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात की अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के स्थापित होने से राज्य में न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं पर भी चर्चा की।

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों पर हरसम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

जगत प्रकाश नड्डा और जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अन्तर्गत अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई

शिमला/शैल। सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला कुल्लू के भुन्तर से राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अन्तर्गत अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दूर-दराज के क्षेत्रों में मरीजों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2010 को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश को मिली अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस चिकित्सा की आपात स्थिति में मरीजों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 50 नई एम्बुलेंस में 40 एम्बुलेंस बेसिक लाइफ स्पोर्ट और दस एडवांस लाइफ

स्पोर्ट सुविधा से लैस है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इन 50 एम्बुलेंस के साथ अब (राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108) एम्बुलेंस का बेड़ा 219 हो गया है।

उन्होंने कहा कि इन 50 नई एम्बुलेंस में से नौ कांगड़ा जिले को, 10-10 मंडी और शिमला, पांच सिरमौर, चार सोलन, दो-दो ऊना और किन्नौर जिला, तीन-तीन बिलासपुर और कुल्लू जिला तथा एक-एक एम्बुलेंस हमीरपुर व लाहौल-स्पीति जिला को उपलब्ध करवाई जाएंगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग सहित अन्य उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पालमपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना, प्रसारण और खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने पालमपुर में हिमाचल प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद किशन कपूर भी उनके साथ मौजूद रहे।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। भारत सरकार ने विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना (SPoCS) के माध्यम से विकास किया है। परियोजना की लागत रु 9.

0 करोड़ है। ऐसे केंद्रों के विकास का मुख्य उद्देश्य देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वभाव विकसित करने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के योगदान को चित्रित करना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में, देश में 25 विज्ञान संग्रहालय/विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। एनसीएसएम ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से पहले ही 22 विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं और बाद में संचालन और रखरखाव के लिए संबंधित राज्य सरकार को सौंपे गये हैं। पालमपुर विज्ञान केंद्र का रखरखाव और संचालन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी छात्रों से आग्रह किया कि वे अनिवार्य रूप से पालमपुर विज्ञान केंद्र का दौरा करें ताकि वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित किया जा सके। उन्होंने खिलाड़ियों के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि विज्ञान के ज्ञान के बिना खिलाड़ी भी इष्टतम परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम को भी सलाह दी कि केंद्र में नई सुविधाएं जोड़ते रहें ऐसा ही एक अतिरिक्त तारामंडल हो सकता है।

उन्होंने कहा कि पालमपुर साइंस सेंटर में 'अनटैम्ड अर्थ' नामक एक विषयगत गैलरी के रूप में स्टार आकर्षण है, जिसमें लगभग 25 इंटरैक्टिव प्रदर्शन हैं। दो सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित संवेदनशील हिमालयी बेल्ट को ध्यान में रखते हुए इसे विशेष रूप से अवधारणा और क्यूरेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश अलग-अलग तीव्रता की भूकंपीय गतिविधियों के लिए प्रवण है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक घटनाएं/आपदाएं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़, हिमस्खलन, जंगल की आग आदि होती हैं जो जीवन और संपत्ति पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। इन इंटरेक्टिव प्रदर्शनों के माध्यम से पृथ्वी द्वारा पेश की जाने वाली इन अविश्वसनीय और भयानक घटनाओं में से कुछ का पता लगा सकते हैं और उनके पीछे के विज्ञान के साथ देख सकते हैं।

अनुराग ने कहा कि केंद्र की अन्य सुविधाएं साइंस पार्क, इनोवेशन हब, पोर्टेबल प्लेनेटेरियम और फन साइंस गैलरी हैं। केंद्र में 3000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र और 2500 वर्ग मीटर प्रदर्शनी स्थान है। केंद्र में अस्थायी प्रदर्शनी लगाने का भी प्रावधान है। वर्तमान में 'यडिजिटल इंडिया' पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ने सहस्राब्दियों के बीच नए उत्साह और रुचि को जगाया है। अद्वितीय पोर्टेबल तारामंडल, जो एक समय में लगभग 25 छात्रों को समायोजित कर सकता है, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करेगा और खगोलीय घटना, रात के आकाश, ग्रहण आदि के पीछे विज्ञान को समझाने में भी आसान होगा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के उत्सव को चिह्नित करने के लिए 15-20 मई 2022 से सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क होगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 19205 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 14 मई, 2022 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य

विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ/आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन एवं पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान किया गया।

इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। आईईसी सामग्री जिसमे जन सुविधा के लिए सभी ग्यारह डीएलएसए के फोन नंबर भी अंकित किए गए थे, को आम जनता के बीच वितरित किया गया, ताकि लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों की पहचान की जा सके।

न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने केलांग में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया और उपमंडल विधिक सेवा समिति, मनाली और लाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलांग जहां पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमे लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों/प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 240 मामलों का निपटारे के लिए चिन्हित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा/ निपटान किया गया और लगभग 53,08,44,573/- रु0 (तिरपन करोड़ आठ लाख चवालीस हजार पाँच सौ तिहत्तर) की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को शाम 5:00 बजे तक वसूल/पुरस्कार दिया गया।

अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार आने वाले समय में मोटर वाहन चालान तथा नेगोशीएबल इन्स्ट्रूमेंट्स मामलों के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।

लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं को समझौता हस्ताक्षरित करने के लिए 31 जुलाई, 2022 तक अतिरिक्त समय

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में विभिन्न कारणों से लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को एकमुश्त रियायत के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं में कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित नहीं हैं, उन्हें 31 जुलाई, 2022 तक अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

यदि किसी कारण से परियोजना निर्माता 31 जुलाई, 2022 तक कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित नहीं कर पाता है तथा वह देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो प्रशासनिक विभाग उसे अतिरिक्त समय देने के लिए अधिकृत होगा।

छह परियोजनाएं जो कि एक मुश्त रियायत योजना से वंचित रह गई थी, उन परियोजनाओं को एक मुश्त रियायत देने का निर्णय लिया गया है।

26 परियोजना निर्माता परियोजना निर्माण के लिए गंभीर नहीं पाये गए तथा उन्होंने एक मुश्त रियायत योजना के अन्तर्गत अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबंध भी हस्ताक्षरित नहीं किए। मंत्रिमण्डल द्वारा इन परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न कारणों से लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 2020 में परियोजना निर्माणकर्ताओं को एक मुश्त रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया था। इसके तहत 224 योजनाएं पात्र थीं, जिनमें से 191 परियोजनाओं के उद्देश्यों को अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित कर पुन: निर्धारित किया गया। अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबंध के अनुसार परियोजनाओं को कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित करने थे। विभिन्न कारणों से कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय पर कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित नहीं कर पायी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या हिमाचल में आप दिल्ली से ही संचालित होगा संयोजक न होने से उठी चर्चा

- क्या कांग्रेस भाजपा से नाराज लोगों के आने से ही विश्वसनीयता बनेगी।
- खालिस्तान प्रकरण पर आप का दो टूक जवाब क्यों नहीं आ रहा?
- मुफ्ती की घोषणाओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से आयेंगे।

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी हिमाचल में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। इस ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल प्रदेश में मंडी और शाहपुर में दो सफल रोड शो रैलियां भी कर चुके हैं। मंडी की रैली के बाद आप ने दिल्ली में दावा किया था कि हिमाचल में भाजपा हाईकमान जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप के इस दावे का जवाब अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल की शाहपुर रैली से पिछली रात आप के प्रदेश संयोजक सहित तीन नेताओं को दिल्ली में नड्डा के आवास पर भाजपा में शामिल करवा दिया। आप की इस टूटन के बाद अभी तक पार्टी प्रदेश में नया संयोजक नामित नहीं कर पायी है। यहां तक की आप के प्रभारी सत्येंद्र जैन के मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र सराज में जो रोड शो करने का ऐलान कर रखा था उसकी तारीख तक अभी घोषित नहीं कर पाये हैं। जो उत्साह केजरीवाल की सफल रैलीयों के बाद आप के पक्ष में प्रदेश में बनने लगा था उसमें अचानक ब्रेक लग गयी है। जबकि मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने का जो ऐजैण्डा लेकर आप चल रही है उसी ऐजैण्डे की कॉपी करते हुये जयराम ठाकुर ने भी मुफ्ती की कुछ घोषणाएं कर दी थी। तब उसके लिये भी श्रेय केजरीवाल को ही दिया गया था। लेकिन इस सबके बाद अब जब आप की गतिविधियों में एक तरह की ब्रेक लग गयी है तो उससे हिमाचल के प्रति आप की गंभीरता और ईमानदारी पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि आप ने दिल्ली में एक पत्रकारवार्ता में दावा किया था कि प्रदेश भाजपा के तीन बड़े नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। बल्कि प्रदेश में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाल कर दर्जनों कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के नाम उछालते हुये यह दावे किये थे कि यह सब लोग उनके संपर्क में चल रहे हैं और जल्दी पार्टी में शामिल होंगे। इसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। इस समय यह आम चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि आप में कोई बड़ा नेता शामिल नही हो रहा है। जितने भी नेताओं से संपर्क साधने की खबरें आती है उन सब में यह आता है कि शामिल होने वाले नेता यह शर्त रख रहें हैं कि पहले उन्हें आप की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाये। संयोगवश इस समय कांग्रेस और भाजपा से नाराज चल रहे सभी छोटे-बड़े नेताओं में यह साहस नहीं है कि वह प्रदेश की वर्तमान समस्याओं पर कोई स्पष्ट राय रख पाये और उनके लिये अपने दलों के नेतृत्व को प्रमाणिक रूप से जिम्मेदार ठहरा सके। जनता को यह स्पष्ट कर पाये कि उनके पास प्रदेश के लिये क्या योजना है और उसे पूरा करने के लिये संसाधन कहां से आयेंगे। आम जनता यदि भाजपा कांग्रेस का विकल्प चाहती है तो उसके लिये विकल्प को विश्वसनीय भी होना पड़ेगा। आप अभी तक प्रदेश में यह विश्वसनीयता बना पाने में सफल नहीं हो पायी है और भाजपा कांग्रेस से नाराज लोगों को लाने से यह विश्वास बन भी नहीं पायेगा। क्योंकि यह आम आदमी की अवधारणा से ही एकदम विपरीत है। आप को आम आदमी की पार्टी बनने के लिये आम आदमी में से ही नेतृत्व निकालना होगा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर अब पंजाब में प्रमाणित करना होगा कि यह सही में आम आदमी है। चुनावी वादे को पूरा करने के लिये केंद्र की सहायता पर निर्भरता से कुछ भी पूरा करना आसान नहीं होगा। हिमाचल में आने से पहले ही शांता कुमार और विजय मनकोटिया के संपर्क में होने के दावे किये जा रहे थे जिसका कोई खंडन नहीं किया गया। जबकि इन्हीं सम्पर्कों ने जो सवाल आप से पूछे और उछालें हैं उनका जवाब आज तक नहीं दिया जा सका है। खालिस्तान को लेकर जो सवाल उठाये गये उनमें लगातार आप को अपरोक्ष में निशाने पर लिया जा रहा है। अब तक इस संद्धर्भ में जो कुछ भी घटा है उसके लिये अपरोक्ष में आप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन आप की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। स्थिति यह बनती जा रही कि आप के चुप रहने से भी इन आक्षेपों से बच नहीं पा रही है। यदि और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी को आगे बढ़ना कठिन हो जायेगा। क्योंकि अब पार्टी के भीतर से ही यह आवाजें उठना शुरू हो गयी है कि दिल्ली से ही हिमाचल का संचालन कब तक होता रहेगा।

नड्डा का फ्रन्ट पर आना जयराम की सफलता या मजबूरी

बार-बार नड्डा के प्रदेश दौरों से उठी चर्चा चरमराते शीर्ष प्रशासन पर नड्डा और अनुराग की चुप्पी क्यों

शिमला/शैल। इस वर्ष के अन्त में प्रदेश विधानसभा के लिये चुनाव होने हैं। भाजपा कांग्रेस और आप तीनों राजनीतिक दलों के लिये यह चुनाव अपने अपने कारणों से महत्वपूर्ण है। क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह भाजपा और कांग्रेस आप से हार चुके हैं। हरियाणा में भाजपा अकेले अपने दम पर सत्ता में नहीं है। ऐसे में यदि हिमाचल भी इनके हाथ से निकल जाता है तो दोनों दलों को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरा आघात लगेगा और उसके परिणाम भी दूरगामी होंगे। कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में बदलाव करके इसमें होने वाले पलायन को रोक लिया है। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा अभी ऐसा कुछ नहीं कर पायी है। जबकि उसके संगठन और सरकार में लम्बे अरसे से बदलाव की चर्चाएं चलती आ रही हैं। जब भाजपा प्रदेश में चारों उपचुनाव हार गयी थी तब नेतृत्व परिवर्तन से लेकर कुछ मंत्रियों को हटाने और कुछ के विभागों में फेरबदल किये जाने की चर्चाएं बहुत तेज हो गयी थी। लेकिन यह सब व्यवहारिक शक्ल नहीं ले पाया है। ऐसा क्यों हुआ है यह विश्लेष्कों के लिए अब तक खोज का विषय बना हुआ है। लेकिन इस पर कलम चलाने से पहले प्रदेश के शीर्ष प्रशासन पर उठते सवालों और उन पर सरकार की रहस्यमई चुप्पी सवालों में है। आज सरकार के मुख्य सचिव से लेकर उनके नीचे के पांच अधिकारी भी सवालों में आ खड़े हुये हैं। क्योंकि दो-दो जगह सरकारी आवास लेने के अतिरिक्त विशेष वेतन का वितीय लाभ भी ले रहे हैं। नियमों के अनुसार यह गंभीर अपराध है। पूरे प्रदेश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री इस पर चुप हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में करीब दो दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें इतने बड़े स्तर पर प्रश्न पत्रों को बेचा गया है। कई तरह के नाम चर्चा में आ रहे हैं। विपक्ष मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री की क्या ऐसी मजबूरी है जो उन्हें कड़ा कदम लेने से रोक रही है। सरकार नेता प्रतिपक्ष को तो मंत्री स्तरीय आवास दे नहीं पायी है लेकिन अपने अफसरों को दिल्ली और शिमला में एक साथ मकान दे कर बैठी हुई है। कर्ज में डूबी सरकार के इस तरह के आचरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देर सवेर अधिकारियों का यह मामला विजिलेंस और अदालत में पहुंचेगा ही। ऐसे में राजनीतिक पंड़ितों के लिए यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिस सरकार का शीर्ष प्रशासन सवालों के कटघरे में खड़ा हो भर्ती परीक्षा के पेपर बेचे जाने के प्रकरण में मामला गिरफ्तारीयों तक पहुंच जाये उस सरकार की साख अपने अंध भक्तों से हटकर आम आदमी की नजर में कहां खड़ी होगी इसका अंदाजा भले ही नेता लोग न लगा पा रहे हो लेकिन आम आदमी पूरी तरह स्पष्ट है। क्योंकि 12% बेरोजगारी की दर के कारण प्रदेश का नाम देश के 6 राज्यों में आ चुका है। इस सबके बावजूद भी जब हाईकमान न हिल रहा हो तो निश्चित रूप से ध्यान जयराम के दिल्ली में बैठे दो वकीलों जे.पी.नड्डा और अनुराग ठाकुर पर जायेगा। क्योंकि नड्डा ने ही जयराम के वकील होने का दावा किया है। इस वकालत नामे पर अमल करते हुये दोनों वकील प्रदेश में किसी न किसी बहाने आने का कार्यक्रम बनाने पर विवश हो गये हैं। अब तो प्रधानमंत्री को भी लाने का जुगाड़ बैठा लिया गया है। भले ही अंतिम क्षणों में प्रधानमंत्री न आ पायें। लेकिन एक बार तो आम कार्यकर्ताओं को बता ही दिया गया है कि प्रधानमंत्री सरकार से कितने खुश हैं। इस परिदृश्य में यह सवाल भी काफी रोचक हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल को पोस्टरों में जगह न देने और धूमल की हार के कारणों की जांच की मांग को सीधे ठुकराने के बाद नड्डा ने प्रदेश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर कैसे ले ली है। नड्डा को फ्रन्ट पर लाकर खड़ा कर देना जयराम की सफलता है या नड्डा की मजबूरी इस पर अभी पर्दा बना हुआ है। लेकिन इस सब में अनुराग की भूमिका आने वाले दिनों में क्या रहती है यह देखना रोचक होगा। क्योंकि जिस तरह से नड्डा प्रदेश में बार-बार आकर रोड शो करने पर मजबूर होते जा रहे हैं उससे प्रदेश में जीत की जिम्मेदारी जयराम से बदलकर नड्डा पर आती जा रही है। इसमें यह देखना भी रोचक होगा कि नड्डा अन्त तक जयराम के साथ खड़े रहते हैं या कुछ कदम चलकर पांव पीछे खींच लेते हैं।